(b) if so, what are the details including the total expenditure incurred, time-schedule and steps taken by Railways in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH); (a) No, Sir.

(b) No expenditure has been incurred by the Railways as the signaling system is not being changed in Bombay. However problems of low voltage power supply are being tackled in coordination with the Electric Supply authorities.

Composition of ACPU

259. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the names of the members of the Agricultural Cost and Price Commission and since when they have so appointed;

(b) whether Government propose to change the structure and membership of ACPC; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR):

(a)

Name	Date of Appointment.
1. Dr. S. S. Johl, Chairman—	20-3-87.
2. Dr. D. S. Tyagi, Member-Secretary—	23-3-85.

Vacancies of two other Members in the Commission are in the process of being filled.

(b) and (c) No, Sir. However, the Government have constituted a Standing Advisory Committee of eminent persons representing farmers interests. The Ministry of Agriculture would regularly interact with this Committee and seek its advice on important matters of policy including support services like prices.

खाद्यान्नों का उत्पादन

260. डा० अबरार अहमद खान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत वर्ष और इस वर्ष के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और इसी अवधि के दौरान राजस्थान में खाद्यान्नों का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में इन वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग के बीच कितना अंतर है ;

हमारा देश किन-किन वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर है और आवश्यकता की पूर्ति के लिये किन-किन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है ;

(ग) देश में तथा राजस्थान में कितनी हैक्टेयर भूमि ऐसी है जो अनुपजाऊ है और जिसे उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है और इस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान कोई धनराशि खर्च की है ; यदि हां, तो कितने क्षेत्र को उपजाऊ भूमि में बदला गया है और भविष्य में इस पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : (क) 1989-90 के लिए विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी राज्यों से देय नहीं हुए हैं । तथापि, अप्रैल, 1990 में आयोजित खरीफ सम्मेलन में बताए गए अनन्तिम अनुमानों के आधार पर, 1989-90 के दौरान सम्पूर्ण देश में तथा पृथक से राजस्थान में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ-साथ पिछले वर्ष अर्थात 1988-89 के संगत आंकड़े (नीचे देखिए) विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) चूंकि देश में खाद्यान्नों की खपत विभिन्न घटकों जैसे आबादी, शहरीकरण की सीमा, आय के स्तर, और मांग की आय लोच, विकल्पों के मूल्यों आदि, पर निर्भर करता है, अतः खपत संबंधी जरूरतों के सही अनुमान उपलब्ध नहीं है । तथापि, कुल मिलाकर देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निर्भर है ।

(ग) और (घ) 1986-87 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए अखिल भारत और इसके साथ-साथ राजस्थान के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्र का नौ-स्तरीय वर्गीकरण अनुबन्ध में दिया गया है । (नीचे देखिए) ।

2. यह विभाग कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिसमें प्रमुख जोर बंजर, कृषि योग्य परती भूमि को कृषि-योग्य क्षेत्रों में परिवर्तित करने पर है । जहां तक राजस्थान का संबंध है, निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

(1) चम्बल, दन्तीवाडा और माही नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना । 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्य को 398 लाख रुपए की राशि मुहैया की गई थी ;

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध । वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्य को 402 लाख रुपए की राशि मुहैया की गई थी ; और

(3) तंगधाटी वाली भूमि का सुधार । वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्य को 1005 लाख रुपए की राशि मुहैया की गई थी ।

3. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड सम्पूर्ण देश के लोगों की भागीदारी के माध्यम से पारिस्थिति की संबंधी खतरों की ओर ध्यान देने तथा मुख्यतया ईंधन और चारे के लिए बायो-मास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीतियां अपना रहा है । जहां तक राजस्थान का संबंध है, कार्यक्रम मूलतया वनरोपण के जरिए वृक्ष और अन्य पौध प्रजातियां उगाने, चरागाह विकास और विभिन्न कृषि-वानिकी माडलों से संबंधित हैं । कृषि-वानिकी माडलों की विभिन्न किस्मों की उपलब्ध प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए सीकर स्थित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इसके लिए, 1989-90 के दौरान 4.18 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है । अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत, वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान 2.08 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है । पहले चार वर्षों के दौरान, 109.63 करोड़ रुपए की राशि पहले ही व्यय की गई है, जबकि 1989-90 के दौरान 16.16 करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया गया था । 1990-91 के लिए, वनरोपण के वास्ते 22.493 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

विवरण

सम्पूर्ण देश में और पृथक-से राजस्थान में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान

(मिलियन मीटरी टन)

फसल	1988-89		1989-90		
	भारत	राजस्थान	भारत	(प्रत्याशित)	राजस्थान*
1	2	3	4	5	6
चावल	70.67	0.19	70.50	—71.20	0.15
गेहूं	53.99	3.96	52.50	—53.80	3.27

1	2	3	4	5	6
मोटे धान्य .	31.89	4.88	33.00	−33.50	3.88
कुल दलहन .	13.70	1.61	14.00	−14.50	1.29
खाद्यान्न . .	170.00	10.64	170.00	−173.00	8.59

*जैसा कि राज्य ने 10-11 अप्रैल, 1990 को आयोजित खरीफ सम्मेलन के दौरान दिया था ।

अनुबंध

राजस्थान और अखिल भारत में भूमि उपयोगिता

प्रतिमान--1986-87 (नवीनतम उपलब्ध)

वर्गीकरण	राजस्थान		अखिल-भारत	
	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत
1. वन . . .	22.5	6.6	66.7	21.9
2. गैर-कृषि कार्य के प्रयोग मे लाया गया क्षेत्र . .	16.6	4.8	20.8	6.8
3. बंजर और अकृष्य भूमि .	28.0	8.2	20.3	6.7
4. स्थायी चरागाह और चराई भूमि	18.2	5.3	12.0	3.9
5. विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अन्तर्गत भूमि	0.2	0.1	3.6	1.2
6. कृषि योग्य परती भूमि .	57.5	16.8	15.6	5.1
7. पुरानी परती भूमि . .	22.4	6.5	10.3	3.4
8. वर्तमान परती भूमि .	22.6	6.6	15.6	5.1
9. बोया गया निवल क्षेत्र .	154.3	45.1	140.1	45.9
10. रिपोर्टिंग क्षेत्र . .	342.3	100.0	305.0	100.0

Increase in the prices of Vanaspati and other edible oils

261. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have recently warned hoarders and speculators against creation of artificial price rise in Vanaspati and other oils;

(b) whether the prices of Vanaspati and other edible oils have increased